

दैनिक रोकटोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

मुंबई ट्रेन धमाके मामले में अभियोजक नियुक्त नहीं होने पर अदालत ने

महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की!

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने 2006 के मुंबई सिलसिलेवार ट्रेन विस्फोट मामले से जुड़ी अपीलों में प्रतिनिधित्व करने के लिए नए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) की नियुक्ति नहीं करने पर बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि सरकार मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। एक ओर, निचली अदालत ने 2015 में इस मामले में पांच आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन इसकी पुष्टि के साथ-साथ आरोपियों द्वारा दायर अपील पर उच्च न्यायालय में सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि 11 जुलाई, 2006 को मुंबई में शाम के समय लोकल ट्रेनों में सात विस्फोट हुए, जिसमें 180 से अधिक लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। जब अपीलें बुधवार को सुनवाई के लिए आईं, तो अदालत को सूचित किया गया कि राज्य सरकार ने अभी तक एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता



राजा ठाकरे को एसपीपी नियुक्त किया गया था क्योंकि उन्होंने मुकदमे के दौरान अभियोजक के रूप में कार्य किया था। लेकिन उन्होंने अपीलीय स्तर पर एसपीपी के रूप में कार्य न करने की इच्छा व्यक्त की, इसलिए

सुनवाई स्थगित कर दी गई। सरकार ने फिर से ठाकरे से संपर्क किया और उनसे जानकारी लेने का अनुरोध किया। लेकिन अदालत को बताया गया कि उनकी नियुक्ति की शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं। बुधवार को जब सरकार ने और समय मांगा तो पीठ ने नाराजगी जाहिर की। न्यायधीशों ने कहा, "क्या आप इन अपीलों के साथ इसी तरह व्यवहार कर रहे हैं? सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। हम कल सुबह राज्य के गृह विभाग के मुख्य सचिव को बुलाकर जवाब मांगेंगे।"

मुंबई की पूर्व महापौर पेडणेकर को गिरफ्तारी से एक महीने की अंतरिम राहत!

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा...

मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कोविड-19 संक्रमण से अपनी जान गंवाने वाले मरीजों के शव को रखने के लिए 'बॉडी बैग' की खरीद में कथित घोटाले के मामले में मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर को चार सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। न्यायमूर्ति एनजे जमादार की एकल पीठ ने पेडणेकर को राहत देते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है और इस स्तर पर हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, "मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान हिरासत में पूछताछ के मुद्दे



पर विचार किया जा सकता है। मैं चार सप्ताह की अवधि के लिए आवेदक (पेडणेकर) की स्वतंत्रता की रक्षा के विचार से सहमत हूँ।" उच्च न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में पेडणेकर को 30,000 रुपये का निजी मुचलका भरने के बाद रिहा किया

जाएगा।

अदालत ने पेडणेकर को मामले की जांच में सहयोग करने और 11, 13 और 16 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक पूछताछ के लिए शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के सामने पेश होने का निर्देश दिया। पीठ इस मामले पर चार हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई करेगी। पिछले हफ्ते एक सत्र अदालत की ओर से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद पेडणेकर ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। सत्र अदालत ने कहा था कि पेडणेकर पर सार्वजनिक धन से जुड़े आर्थिक अपराध का आरोप है जिसमें मोटी रकम शामिल है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता किरीट सोमैया की शिकायत के आधार पर पेडणेकर और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 420 (धोखाधड़ी) और 120 (बी) (आपराधिक साजिश) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

चेंबूर डायमंड गार्डन में शुरू सौंदर्यकारण कार्यों का हुआ निरक्षण

मुंबई कुछ दिनों पूर्व डायमंड गार्डन में शुरू सौंदर्यकरण के कार्यों को धीमे गति सहित चटिया दर्जे का कार्य स्थानीय मॉर्निंग वॉक पर आने वाले वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत पर मनसे ने डायमंड गार्डन में मनपा कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व भाजपा नगरसेविका आशा मराठे ने मनपा के वरिष्ठ संबंधित गार्डन विभाग के अधिकारी शशि बेमबड़े कार्यकारी अभियंता गार्डन विभाग भायखल्ला, लोकेश उपाभियंता गार्डन विभाग भायखल्ला को



दिनांक 6-9-2023 को सुबह आठ बजे चेंबूर के बहुचर्चित डायमंड गार्डन में शुरू सौंदर्यकरण कार्यों का निरक्षण किया। गार्डन पर मौजूद स्थानीय रहवासीय

जनता को अधिकारियों ने संबोधित करते हुए कार्यों से अवगत करवाया तथा शुरू कार्यों में सहयोग करने की अपील किया। वहीं पूर्व भाजपा नगरसेविका आशा मराठे ने कहा की जनहित के कार्यों में दजेदार कार्य ही करवाया जायेगा। जिसका मैं आप स्थानीय नागरिकों को आश्वस्त करवाती हूँ। उल्लेखनीय तौर पर डायमंड गार्डन परिसर के आस पास बिल्डिंगोंबक सोसाइटी के बड़ी संख्या में जमा नागरिकों ने गार्डन का सौंदर्यकरण कार्य करवाने के लिए आभार व्यक्त किया।

मुंबई पुलिस ने लोकशाही समाचार चैनल के संपादक कमलेश सुतार और यूट्यूबर अनिल थट्टे के खिलाफ FIR दर्ज की

मुंबई : मंगलवार को मुंबई पुलिस ने लोकशाही समाचार चैनल के प्रधान संपादक कमलेश सुतार और यूट्यूबर अनिल थट्टे के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। उन पर स्पष्ट सामग्री वाला एक वीडियो प्रसारित करने का आरोप है, जिसमें भाजपा नेता किरीट सोमैया शामिल हैं। सोमैया ने बुधवार को मुंबई पुलिस पूर्वी क्षेत्र साइबर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उल्लेख किया कि वीडियो को लोकशाही चैनल पर इसके संपादक, कमलेश सुतार द्वारा प्रसारित किया गया था, जबकि अनिल थट्टे ने इसे अपने यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम किया था। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विवाद के बाद मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को वीडियो की जांच करने के लिए



कहा गया था। इस साल जुलाई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें पूर्व सांसद को वीडियो कॉल पर आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। मराठी समाचार चैनल 'लोकशाही' ने वीडियो फुटेज को अपने कब्जे में लेने का दावा किया था, हालांकि उन्होंने स्पष्ट सामग्री को धुंधला करके और इसमें शामिल महिला की पहचान की रक्षा करके सावधानी बरती थी। एक लाइव शो के दौरान, लोकशाही के संपादक कमलेश सुतार ने किसी की निजता पर हमला नहीं करने, बल्कि वीडियो की प्रामाणिकता और

किसी भी संबंधित शिकायत के संबंध में सोमैया से स्पष्टीकरण मांगने का इरादा व्यक्त किया था। चैनल ने इस बात पर जोर दिया था कि हालांकि इस तरह की सामग्री के प्रसारण को गोपनीयता के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है, एक प्रमुख राजनीतिक दल के भीतर सोमैया की स्थिति के महत्व के कारण किसी भी संभावित निगरानी या गलत काम को संबोधित करना आवश्यक है। चैनल ने सोमैया जैसी शख्सियत से जुड़ी समझौतापूर्ण स्थिति पर आश्चर्य व्यक्त किया था, जो खुद अक्सर विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार और कदाचार का आरोप लगाते रहते हैं, जिससे साजिश की संभावना बढ़ जाती है। इस वीडियो ने स्वाभाविक रूप से राज्य में राजनीतिक टकराव पैदा कर दिया था, विरोधियों ने 'अश्लील' गतिविधियों में शामिल होने के लिए सोमैया के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की थी।

रोकटोकलेखनी
Daily Hindi National Newspaper

Sabri Human Welfare Foundation (NGO)
Regd. No. F-712150

Happy
Janmashtami

Fail to achieve your goal, change the strategy not goal

Faisal Shaikh
President : Sabri Human Welfare Foundation NGO
Chief Editor : Rokthok Lekhani Newspaper

+91 99877 75650
editor@rokhoklekhani.com
Mahim Mumbai 400016

@faisalsk_91 @faisalsk_91 @faisalsk_91

संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

मोहब्बत की दुकान पर नफरत का माल

राजनीतिक मजबूरियां राजनीतिक दलों से क्या-क्या नहीं करवातीं, इसकी कल्पना करना कठिन है। 1997 में जब इंद्र कुमार गुजराल की साझा सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, तभी राजीव गांधी हत्याकांड की जांच कर रहे जैन

आयोग की अंतरिम रपट लीक हो गई। इस रपट में कहा गया था कि राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचने वालों को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक प्रमुख करुणानिधि को भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए। तब द्रमुक के कई नेता गुजराल सरकार में मंत्री थे। कांग्रेस ने कहा कि इन सभी मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। गुजराल ने इन्कार किया। नतीजे में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई तथा देश में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े, पर बाद में यही द्रमुक कांग्रेस की एक मजबूत सहयोगी बन गई। वह आइएनडीआइए का भी प्रमुख घटक है। अब करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और उनके बेटे उदयनिधि मंत्री हैं। बीते दिनों उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म मलेरिया, डेंगू और कोरोना की तरह है और इसका विरोध नहीं, बल्कि खात्मा किया जाना चाहिए। उनके इस बयान पर जब तीखी प्रतिक्रियाएं आईं, तब भी वह अपने कथन पर अडिग रहे। चूंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए उनकी पार्टी क्या करेगी, इसलिए जानना कठिन है कि वह किसी वैक्सीन का सहारा लेंगे या फिर कोई रसायन या औषधि तैयार कराएंगे? वह कुछ भी करें, मगर यह आश्चर्यजनक है कि ममता बनर्जी को छोड़कर आइएनडीआइए के घटकों के किसी बड़े नेता ने उदयनिधि के नफरती बयान की निंदा नहीं की। लालू यादव, नीतीश कुमार से लेकर हनुमान भक्त अखिलेश यादव और शिव भक्त राहुल गांधी भी मौन साध गए। यह जरूरी नहीं कि राहुल हर मुद्दे पर कुछ कहें ही, पर उनका मौन इसलिए हैरान करता है, क्योंकि वह मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते हैं। क्या उन्हें इसका भान है कि उनकी इस दुकान के एक भागीदार उसमें कितना नफरती माल बेच रहे हैं? क्या उदयनिधि का बयान वाकई ह्युजेगा भारत-जीतेगा इंडिया नारे के अनुरूप है?

कांग्रेस के एक-दो नेताओं ने उदयनिधि के बयान से असहमति जताई तो कुछ ने उनका न केवल बचाव किया, बल्कि उन्हें सही भी ठहराया। इनमें मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे एवं कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे और पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम प्रमुख हैं। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक तरह से उदयनिधि का समर्थन करते हुए कहा, ह्यहम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि सभी दलों को अपनी बात कहने की आजादी है। साफ है कि उन्होंने उदयनिधि के बयान पर अभिव्यक्ति की आजादी की चादर डाल दी। यदि उदयनिधि का द्वेष भरा बयान अभिव्यक्ति की आजादी है तो फिर हेट स्पीच क्या होती है? हेट स्पीच पर हल्ला मचाने वाले सेक्युलर-लिबरल तत्वों की चुप्पी पर भी गौर करें।

+91 99877 75650

editor@rokhoklekhaninews.com

Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

दहीहांडी दिवस पर सभी कर्मचारियों को मुख्यालय न छोड़ने का मनपा प्रशासन का अजीब आदेश यूनियन पदाधिकारियों ने व्यक्ति की नाराजगी...

मुस्तकीम खान
भिंवंडी : महाराष्ट्र सरकार ने इसके मद्देनजर मनाए जाने वाले जन्माष्टमी और दही हांडी के अवसर पर विशेष अवकाश की घोषणा की है। और इस तरह के आदेश कोंकण कमिश्नर की ओर से पूरे कोंकण डिविजन के सरकारी अर्धसरकारी कार्यालयों को जारी किए गए हैं। इस बीच भिवंडी मनपा आयुक्त अजय वैद्य के आदेश पर उपायुक्त मुख्यालय डॉ. सचिन माने ने भिवंडी मनपा के सभी नियंत्रण अधिकारियों, विभाग के अधिकारियों और उनके अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारियों को संपर्क में रहने और मुख्यालय नहीं छोड़ने के विशेष आदेश दिए हैं। कोंकण आयुक्त ने दही हांडी



के अवसर पर छुट्टी घोषित करने का आदेश दिया है, जबकि भिवंडी शहर में सरकारी कार्यालय बंद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दही हांडी जैसे त्योहार पर भिवंडी शहर में आ रहे हैं। ऐसे में मनपा उपायुक्त सचिन माने ने आदेश दिया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी संपर्क में रहें और मुख्यालय न छोड़ें। ऐसी

नाराजगी नगर मनपा के अधिकारियों और कर्मचारियों में फैल गई है। दिलचस्प बात यह है कि भिवंडी मनपा आयुक्त अजय वैद्य ने पिछले चार शनिवार को सभी कार्यालय खोलकर कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है इस संबंध में जब उपायुक्त डॉ. सचिन माने से संपर्क किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि दही हांडी

के अवसर पर सभी लोग छुट्टी पर हैं और संपर्क में रहने तथा मुख्यालय नहीं छोड़ने यानी शहर नहीं छोड़ने का आदेश जारी किया गया है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भानुदास भसाले ने मनपा आयुक्त को पत्र देकर बयान दिया है कि कर्मचारियों को शनिवार और अन्य छुट्टियों के दिन काम पर नहीं बुलाया जाए। भानुदास भसाले ने आरोप लगाया है कि छुट्टी के दिन किसी को भी काम पर नहीं बुलाया जाए बिना अनुमति के मुख्यालय ना छोड़ने का अर्थ है कि कार्यालय में उपस्थित रहना। भानुदास भसाले ने आरोप लगाया है कि इस तरह के आदेश से कर्मचारियों और श्रमिक वर्ग के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।

भिंवंडी मनपा के सहायक आयुक्त के साथ हाथापाई करने वाले दो पहुंचे हवालालत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची मनपा टीम के काम में उत्पन्न किया था व्यवधान



मुस्तकीम खान संवाददाता
भिंवंडी : भिवंडी के चिंचिंद्रा इलाके में अवैध निर्माण ध्वस्त करने गए सहायक आयुक्त के साथ धक्का मुक्की व गाली गलौच करना दो अवैध निर्माणकर्ताओं नप गए हैं। मनपा अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा निर्माण करने व गाली गलौच का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

भिंवंडी मनपा प्रभाग समिति क्रमांक एक के सहायक आयुक्त सुदाम जाधव अपने अतिक्रमण टीम के साथ एक सितंबर को दोपहर में 12 बजे चांचिंद्रा गांव के सर्वे नंबर

95/1, 95/5, 39/1 पर बन रहे अवैध मकानों को ध्वस्त करने लिए गये हुए थे। इस दौरान सूचना मिलते ही उक्त स्थान पर बिना अनुमति के मकान बनाने वाले इरफान खान व शकील अंसारी पहुंच गए और मनपा के तोड़कर कार्यवाई का विरोध करने लगे इतना ही नहीं उक्त लोगों ने सहायक आयुक्त सुदाम जाधव के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किया। यही नहीं शकील ने सुदाम जाधव को धक्का भी दिया, साथ ही उन्होंने धमकी भी दी कि यदि दोबारा तोड़कर करने के लिए वापस आए तो तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा। तुम को निर्लंबित भी करवा दूंगा जिसके बाद शिकायत सहायक आयुक्त ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे और दोनों के खिलाफ भादवि की धारा 353, 332, 504, 506, 34 के तहत केस दर्ज कराया जिसके बाद दूसरे दिन शांतिनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जिसे अदालत ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। केस की तहकीकात महिला पुलिस उप निरीक्षक शीतल लोमटे कर रही है।

पहली पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए पति ने कराया अपनी ही बेटी का DNA टेस्ट पति, ससुर समेत 7 लोगों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज।

मुस्तकीम खान संवाददाता
भिंवंडी : भिवंडी शहर में दहेज के लिए प्रताड़ना की घटना आम बात हो गई है लेकिन अब भिवंडी में एक चौकाने वाली घटना सामने आई है जहां पति ने पहली पत्नी के चरित्र पर संदेह कर अपनी ही बेटी का डीएनए टेस्ट कराया है वही पीड़िता के ससुराल वालों द्वारा मैहर से पैसे लाने के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। इस मामले में 35 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति और 7 ससुराल वालों के खिलाफ शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शांतिनगर पुलिस ने इन सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिस में पति रियाज अहमद हातिम अंसारी 40, ससुर हातिम अंसारी 65, सास शमीमाबानो अंसारी 55, देवर हाशिम अंसारी 42, एजाज अंसारी 30, हिनाकौसर अंसारी 35, नन्द नसरीन अंसारी 35 ससुराल वालों के नाम हैं, जिन पर शांति नगर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीड़िता के पति रियाज और उसके ससुराल वालों ने आपस में साठ गांठ कर के 9 सितंबर 2017 से 12 नवंबर 2017 के दरम्यान



शादी के बाद पीड़िता को पैसे के रूप में दहेज लाने के लिए मानसिक और शारीरिक यातनाएं देकर तकादा करने लगे लेकिन विवाहिता ने मैहर से पैसे लाने से इनकार कर दिया जिस के बाद पति ने विवाहिता के चरित्र पर शक करते हुए खुद की बेटी का डीएनए टेस्ट कराया है जबकि पीड़ित विवाहिता ने अपनी फरियाद में यह भी आरोप लगाया है कि उसके पति ने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर ली है, आखिरकार इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता शांतिनगर पुलिस स्टेशन पहुंच कर अपने पति समेत 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ 498 (ए), 494 समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच मपोह एम. एम. फर्डे कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के मजदूर की औरंगाबाद में मौत! भवन निर्माण के दौरान बोरिंग का काम कर रहा था... छत से गिरा

मुंबई : औरंगाबाद में मंगलवार रात छत से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। हादसा जिले के नगर थाना क्षेत्र के ब्लॉक कॉलोनी में हुआ। जहां भवन निर्माण के दौरान बोरिंग का काम कर रहे मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान महाराष्ट्र के यवतमाड़ जिले के वनी थाना क्षेत्र के वनी गांव निवासी श्री राम कोबे के 21 वर्षीय पुत्र शंकर कोबे के रूप में की गई है।



सूचना मिलते ही सभी मजदूरों में अफरा तफरी मच गई और इसकी जानकारी बोरवेल के मालिक को देते हुए मजदूर को सदर अस्पताल

लाया। मगर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर नगर थाना के दारोगा अरविंद

प्राप्त जानकारी के अनुसार शंकर औरंगाबाद में बोरिंग के काम से जुड़ा हुआ था। मंगलवार की रात काम के समापन के बाद वह अपने तीन साथियों के साथ कार्य स्थल के बगल ही निर्माणाधीन भवन के छत की सेटिंग पर सोने चला गया और छत से गिर गया लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं हो पाई। रात्रि में उधर से गुजर रहे मुहल्ले के एक युवक ने शंकर को गिरा देखा तो इसकी सूचना अन्य मजदूर जो बोरिंग के काम में लगे हुए थे उनको दी।

दही हंडी के अवसर पर तीन हजार पुलिसकर्मि तैनात



मुंबई : ठाणे जिले में दही हंडी के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब तीन हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसमें एंटी बम स्व्वाड, वायरलेस मैसेजिंग विभाग, राज्य रिजर्व बल की दो इकाइयां, सादे कपड़ों में पुलिस आदि का समावेश है। बता दें कि ठाणे

में गोपालकाला के अवसर पर विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों द्वारा दही हंडी का आयोजन किया जाता है। मुंबई, उपनगरों, ठाणे, रायगड जिलों से गोविंदा की टीमों दही हंडी फोड़ने के लिए शहर में आ रही हैं। इस पृष्ठभूमि में ठाणे पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगभग तीन हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात करेगी। दही हंडी के मौके पर आयोजक और गोविंदा टीमों नियमों का उल्लंघन न करें, इसके लिए पुलिस गश्त करेगी। इसमें राज्य रिजर्व पुलिस बल की दो इकाइयां, तीन बम खोजी दस्ते, वायरलेस मैसेजिंग विभाग को भी तैनात किया जाएगा।

देश का नाम बदलने का अधिकार किसी को नहीं : पवार

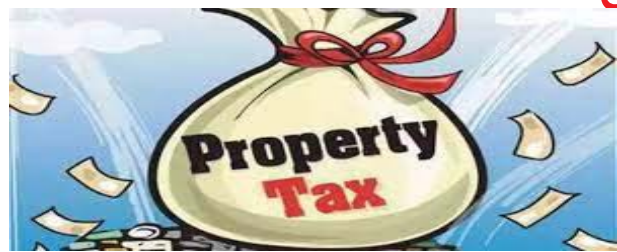
मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि किसी को भी देश का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। उनकी यह टिप्पणी कांग्रेस के उस दावे के बाद आई है कि जी-20 रात्रिभोज के निमंत्रण में राष्ट्रपति को 'प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया' की जगह 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' कहकर संबोधित किया गया है।



जलगांव जिले के दौरे पर पहुंचे शरद पवार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार 18 सितंबर से बुलाए गए विशेष सत्र में कुछ अहम बिल पेश करने जा रही है। चर्चा है कि इस सत्र में भारतीय संविधान से इंडिया शब्द हटाने के लिए एक विधेयक लाया जाएगा। केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में विधेयक लाकर इंडिया गठबंधन का इंडिया शब्द बदलने की तैयारी कर रही है। शरद पवार ने केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी है और कहा है कि इस नाम को बदलने का अधिकार किसी को नहीं है।

पवार ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुधवार को बुलाई गई बैठक में उन पार्टियों के प्रमुखों के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जाएगा जो विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' का हिस्सा हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या संविधान में 'इंडिया' का नाम बदला जाएगा, पवार ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पवार ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुधवार को 'इंडिया' गठबंधन के सभी दलों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि बैठक में इस पर विचार-विमर्श होगा, लेकिन (देश का) नाम बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई भी नाम को नहीं बदल सकता। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में 'राज्यों के संघ' पर हमला हो रहा है और दावा किया कि जी-20 रात्रिभोज के निमंत्रण में राष्ट्रपति को 'प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया' की जगह 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' बताया गया है। जी-20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में नौ से 10 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जा रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित दुनिया भर के कई राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग ले रहे हैं।

मंडराने लगा संपत्ति कर वृद्धि का संकट



मुंबई : आम आदमी दिन-ब-दिन बढ़ती महंगाई से जहां त्रस्त हो चुका है, वहीं अब मनपा ने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में मुंबईकरों पर संपत्ति कर वृद्धि का संकट मंडराने लगा है। दूसरी ओर महानगरपालिका अधिनियम के अनुसार हर पांच वर्ष में होनेवाली कर वृद्धि पिछले तीन वर्षों से नहीं की गई है। ऐसे में 2023-2024 के लिए कर बढ़ाने की कार्यवाही शुरू की गई है। यह वृद्धि लगभग 15 प्रतिशत होने की संभावना है। मनपा ने देरें तय करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति के लिए निविदा आमंत्रित की है। हालांकि, इस कर वृद्धि का विरोध होने की भी आशंका है।

मुंबई में हर पांच साल में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जाता है। साल 2014

रूप में नियुक्त किया जाता है, क्योंकि कर वृद्धि का मनपा की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका निष्पक्ष अध्ययन करना आवश्यक है। इसके लिए अकाउंटेंट नियुक्त किया जाएगा और 32.15 लाख रुपए की निविदा आमंत्रित की गई है।

अगले दो साल यानी साल 2023 से 2024 तक टैक्स बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसका मसौदा मनपा के कर मूल्यांकन और संकलन विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। मनपा अधिनियम हर पांच साल में 80 प्रतिशत कर वृद्धि का प्रावधान करता है। हालांकि, कर मूल्यांकन व संकलन विभाग का कहना है कि सामान्य तौर पर 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही है, ताकि नागरिकों पर अधिक बोझ न पड़े। संपत्ति कर में वृद्धि उस क्षेत्र की रेडिरेकर दर के अनुसार तय की जाएगी। इस बीच आनेवाले समय में मनपा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह दर वृद्धि तुरंत या चुनाव के बाद लागू की जाएगी।

90 साल बाद सुलझी गोरेगांव की सरला अहिरे की हत्या की गुत्थी...

मुंबई : गोरेगांव की सरला अहिरे की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस हत्याकांड में उसके प्रेमी प्रवीण दभलकर को अरेस्ट किया गया है। सरला की 26 नवंबर 2013 को बोरिवली के नेशनल पार्क में लाश मिली थी। पुलिस का कहना है कि सरला का मर्डर 26 नवंबर को किया गया था। सरला गोरेगांव के तीन डोंगरी इलाके के तानजी नगर मोहल्ले में अपनी मां और बहन के साथ रहती थी। वह गोरेगांव में ही किसी इमिग्रेशन जूलरी फर्म में काम करती थी। वह 26 नवंबर को दोपहर घर से निकली, पर जब देर रात तक घर वापस नहीं पहुंची तो उसके परिजनों ने पुलिस में मिसिंग की शिकायत की थी।



पुलिस के अनुसार, आरोपी प्रवीण भी गोरेगांव का ही रहनेवाला है और उसका सरला से काफी दिनों से अफेयर था। प्रवीण शादीशुदा था, इसलिए अफेयर के बावजूद वह सरला से शादी नहीं करना चाहता था, जबकि सरला उस पर इसके लिए दबाव डाल रही थी। इसी वजह से उसने सरला के कत्ल की साजिश इस तरह से रची कि शक उस

करे। इस पर प्रवीण ने कॉल नहीं, बल्कि सरला को मराठी में एसएमएस किया, जिसका हिंदी भावार्थ था कि मुझे कॉल करो। जब सरला का फिर भी कॉल नहीं आया तो प्रवीण, सरला के परिवारवालों को लेकर खुद पुलिस स्टेशन मिसिंग की शिकायत दर्ज कराने गया था। हालांकि, सरला को कॉल करने की बजाय एसएमएस करने से वह पुलिस के शक के घेरे में आ गया। इसके बाद प्रवीण से लगातार सख्त पूछताछ की जाती रही, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, प्रवीण की पत्नी और परिवार सभी को यह तो पता था कि प्रवीण सरला से नियमित बात करता है, पर सब लोग यह समझते रहे कि दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसका ही फायदा उठाकर प्रवीण ने अपनी शादीशुदा होने का बात छिपाए रखा और उससे बचने के लिए सरला की हत्या कर दी। अंधेरी कोर्ट में चले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है।

उद्धव के गढ़ में राज ठाकरे की एंट्री...

इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी... शिवसेना में टूट का मिलेगा फायदा?

मुंबई : आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एमएनएस (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) परीक्षण करती नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि मनसे ने कोंकण के रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक स्थिति और पार्टी की राजनीतिक ताकत का आकलन करना शुरू कर दिया है। तो क्या मनसे ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए परीक्षण शुरू कर दिया है? ऐसा सवाल खड़ा हो



गया है। इस बीच इस सवाल पर बात करते हुए कोंकण के एमएनएस के कुछ नेताओं ने इसकी पुष्टि की है। आने

वाले समय में मनसे तालुका पर चर्चा करने और अपनी राजनीतिक ताकत का परीक्षण करने के लिए रायगढ़ में विधानसभा क्षेत्र और तालुका स्तर पर बैठकें करेगी। तो क्या मनसे कोंकण के रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी? इसको लेकर चर्चा जोरों से शुरू हो गई है। कोंकण शिवसेना का गढ़ है। फिलहाल रायगढ़ लोकसभा सीट से अजित पवार ग्रुप के सुनील तटकरे सांसद हैं। तो सुनील तटकरे के सामने कौन होगा उम्मीदवार?

राज ठाकरे का कोंकण दौरा और जागर आंदोलन...

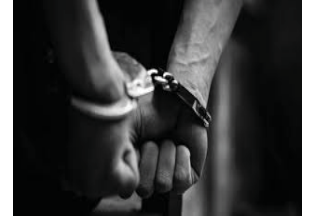
पिछले छह से आठ महीनों में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने दो बार कोंकण का दौरा किया। रत्नागिरी में एक सार्वजनिक बैठक भी आयोजित की गई। कुछ संगठनात्मक परिवर्तन भी किये गये। जो कार्यकर्ता गुटों से लड़ रहे थे, उन्हें निशाने पर लिया गया। अपने दौरे के दौरान और रत्नागिरी में हुई बैठक के दौरान राज ठाकरे ने कोंकणी व्यक्ति का समर्थन किया। अपने भाषणों के दौरान उन्होंने कोंकण के कुछ बुनियादी मुद्दों को छुआ। तो राज ठाकरे के मन में क्या चल रहा है? मनसे स्थानीय स्वशासन, विधानसभा या लोकसभा चुनाव किन निर्वाचन क्षेत्रों में लड़ेगी? इसको लेकर कुछ सवाल और चर्चा भी हुई।

सेना के गढ़ में मनसे की चुनौती?

कोंकण को शिवसेना का गढ़ कहा जाता है। रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तीन जिलों में शिवसेना की ताकत है। तो एक कोंकणी आदमी, जो कि शिवसेना का पारंपरिक मतदाता है, शिवसेना के गढ़ में मनसे को कितना समर्थन देगा? यह भविष्य में स्पष्ट हो जायेगा। खास बात ये है कि क्या शिवसेना में बड़े नुकसान के बाद एमएनएस को फायदा होगा? आखिर क्या होगी एमएनएस की रणनीति? क्या राज ठाकरे कोंकणी को लुभाने में सफल होंगे? ऐसे कई सवाल अब उठ रहे हैं। लेकिन आने वाले चुनाव और उनके नतीजे इसका जवाब जरूर देंगे।

ठाणे/ ७५ हजार रुपए की रिश्वत की मांग... इंजीनियर तीन साथियों के साथ गिरफ्तार

मुंबई : ठाणे जिले के अंबरनाथ में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करने गई टीम में शामिल अधिकारियों द्वारा बिजली चोरी करने वाले ग्राहक से ७५ हजार रुपए की रिश्वत की मांग करने की घटना सामने आई है। मामले की सूचना के बाद ठाणे रिश्वत निरोधक विभाग की टीम ने एक इंजीनियर को उसके तीन साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हेमंत गोविंद तिडके (३४) कल्याण के विद्युत वितरण कार्यालय में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। उनके साथ तीन आरोपियों में अंबरनाथ जूनियर क्लर्क सागर ठाकुर (३२), पांडुरंग देवीदास सूर्यवंशी (४२) और नितिन साल्वे (३५) को गिरफ्तार किया गया है। इंजीनियर की टीम ने शिकायत कर्ता के घर का लाइट मीटर भी जप्त कर लिया था। बिजली अधिकारियों ने मीटर



में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पिछले ३ साल का लाइट बिल ३ से ४ लाख रुपए जुमाने के साथ भरने की बात कही। साथ ही आरोपियों ने यह कहते हुए ७५ हजार की रिश्वत की मांग की कि यदि वे यह रकम नहीं देना चाहते हैं तो वे एक लाख तक का ही बिल भेजेंगे। संबंधित ग्राहक की शिकायत के अनुसार ठाणे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारियों ने जाल बिछाया और चारों को गिरफ्तार कर लिया। अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आगे मामले की छानबीन पुलिस कर रही है।

एक और बैंक बिकने वाला है...सरकार ने इच्छुक पार्टियों से बोलियां मंगाई



मुंबई : केंद्र की भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद से लगातार निजीकरण पर ध्यान दे रही है। एक-एक करके सरकारी कंपनियों को और बैंकों को बेच रही है। अब खबर आ रही है कि एक और बैंक बिकने वाला है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। सरकार जल्दी ही आईडीबीआई बैंक के लिए एसेट वैल्यूअर को नियुक्त करेगी। इसके लिए सरकार ने इच्छुक पार्टियों से बोलियां मंगाई है। इसके लिए ९ अक्टूबर तक बोली लगाई जा सकती है। सरकारी दस्तावेज के अनुसार, चुने जाने वाले एसेट वैल्यूअर को बैंक की संपत्तियों का मूल्यांकन करना

होगा और बिक्री की पूरी प्रक्रिया के दौरान मदद मुहैया करानी होगी। इससे पहले सूत्रों द्वारा दावा किया गया था कि सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी की संभावित बिक्री को अगले वित्त वर्ष के लिए टाल सकती है। हालांकि, ताजा कदम से ऐसा लगता है कि सरकार पुरानी योजना के हिसाब से ही चल रही है। सरकार की योजना है कि दिसंबर तक आईडीबीआई बैंक के लिए फाइनेंशियल बिड इश्यू किए जाएं और चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही तक यानी मार्च २०२४ तक आईडीबीआई बैंक की अपनी हिस्सेदारी बेच दे। इसके लिए जुलाई में प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई थी। अब एसेट वैल्यूअर की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। सरकार को आईडीबीआई बैंक की अपनी हिस्सेदारी को बेचकर १५ हजार करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। इस वित्त वर्ष में सरकार ने विनिवेश से ५१ हजार करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट सेट किया है।

मुंबई लोकल में अचानक भिड़ गए दो यात्री... झगड़ा रोककर तीसरा शख्स बन गया हीरो



मुंबई : मुंबई लोकल ट्रेनों को वहां की लाइफलाइन कहा जाता है। अगर ये रुक जाएं तो आधी मुंबई रुक जाएगी। मुंबई में रहने वाली आधी आबादी इसके सहारे अपनी जिंदगी काटती है। अब चूँकि मुंबई की लगभग आधी आबादी इन ट्रेनों के सहारे रहती है तो फिर यह तो साफ है कि इनमें भीड़ भी काफी रहती होगी। इसी भीड़-भाड़ में कई बार लोगों के बीच बहस भी हो जाती है। कई बार तो बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। अभी सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुंबई लोकल की ट्रेन में अचानक दो लोग एक-दूसरे से बहस करने लगते हैं। बहस इतनी बढ़ जाती है कि नीले टी-शर्ट में मौजूद शख्स दूसरे इंसान को धक्का मार देता है।

जलवायु परिवर्तन, लंग्स की बीमारियों को न्योता...

मुंबई : हिंदुस्थान समेत समूचे विश्व में हो रहा जलवायु परिवर्तन चिंता का विषय बना हुआ है। इसका असर इंसानों से लेकर जानवरों और पशु-पक्षियों पर भी पड़ रहा है। इसके चलते लोगों को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल में किए गए एक शोध में वैज्ञानिकों ने पाया है कि जलवायु परिवर्तन फेफड़ों का दम निकाल सकता है। अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) जैसी फेफड़ों की समस्याओं से पीड़ित बच्चों और वयस्कों को जलवायु परिवर्तन से और अधिक खतरा हो सकता है। यह एक तरह से लंग्स की बीमारियों को न्योता दे रही है।



यूरोपियन रेस्पिरैटरी जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट इस बात का सबूत पेश करती है कि वैश्वे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे हीटवेव, जंगल की आग और बाढ़, दुनियाभर के लाखों लोगों, विशेषकर शिशुओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए सांस लेने में कठिनाई को और बढ़ा देंगे। यूरोपीय रेस्पिरैटरी

सोसाइटी के पर्यावरण और स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर जोराना जोवानोविक एंडर्सन ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन हर किसी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, लेकिन इससे श्वसन रोगी सबसे अधिक असुरक्षित हैं। ये वे लोग हैं, जो पहले से ही सांस लेने में कठिनाई का सामना करते हैं और वे हमारी बदलती जलवायु के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील हैं। उनके लिए जलवायु परिवर्तन खतरनाक साबित होगा। रिपोर्ट के अनुसार, इन प्रभावों में वायुजनित एलर्जी में वृद्धि शामिल है। इनमें लू, सूखा और जंगल की आग जैसी घटनाएं भी शामिल हैं, जिससे अत्यधिक वायु प्रदूषण और धूल भरी आंधियां होती हैं। साथ ही भारी वर्षा और बाढ़ से घर में उच्च

आर्द्रता और फफूंदी भी रोगियों के लिए खतरनाक है। यह रिपोर्ट विशेष रूप से शिशुओं और बच्चों के लिए अतिरिक्त जोखिम पर प्रकाश डालती है, जिनके फेफड़े अभी भी विकसित हो रहे हैं। इस वर्ष दुनियाभर में उच्च तापमान के नए रिकॉर्ड बने हैं। यूरोप में लू, विनाशकारी जंगल की आग, बारिश, तूफान और बाढ़ का अनुभव हुआ है। प्रोफेसर एंडर्सन के मुताबिक, श्वसन डॉक्टरों और नर्सों के रूप में हमें इन नए जोखिमों के बारे में जागरूक रहने और मरीजों को पीड़ा को कम करने में मदद करने की जरूरत है। हमें अपने मरीजों को जोखिमों के बारे में भी समझाने की जरूरत है, ताकि वे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से खुद को बचा सकें।